Popular Front of India

G-78, 2nd Floor, Shaheen Bagh, Kalindikunj, Noida Road, New Delhi- 110025
website: www.popularfrontindia.org email: popularfrontmail@gmail.com Tel: 011- 29949902

14 सितम्बर 2017

कालीकट में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी बयान

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के चेयरमैन ई. अबूबकर ने कल कालीकट, केरल में आयोजित एक मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पॉपुलर फ्रंट की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए कुछ मीडिया में प्रसारित की जा रही हालिया ख़बरों का सिलसिला पूर्ण रूप से लोकतंत्र विरोधी है। संगठन ऐसी तमाम कोशिशों को रोकने हेतु सभी कानूनी तरीके अपनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केरल प्रदेश अध्यक्ष नसरूद्दीन एलामरम भी मौजूद रहे। लीडरों ने यह भी ऐलान किया कि संगठन की पॉलीसी और नज़रिये पर रोशनी डालने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में जनसभाओं का आयोजन किया जाएगा।

नीचे पूरा बयान लिखा जाता है:

पॉपुलर फ्रंट की गतिविधियों को रोकने की कोशिश, लोकतंत्र विरोधी

ऐसा लगता है कि सत्ता में बैठी दाएं बाजू की हिंदुत्वा सरकार, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बदनाम करने और उसके खिलाफ झूटे प्रोपगंडे जैसे लोकतंत्र एवं संविधान विरोधी तरीके अपना कर संगठन की गतिविधियों को रोकने की कोशिश कर रही है। हम इस तरह की तमाम कोशिशों की कड़ी निंदा करते हैं। पॉपुलर फ्रंट के खिलाफ संसनीख़ेज़ कहानियों के नए एपिसोड की शुरूआत, टाइम्स ग्रुप से जुड़ी विभिन्न मीडिया के द्वारा की गई। जिसकी बुनियाद जाँच एजेंसी के द्वारा गृह मंत्रालय को कथित तौर पर सौंपी गई दस्तावेज़ों को बनाया गया है। इन दस्तावेज़ों को 2008 में यूएपीए के कानून में किये गए संशोधनों के हिस्से के तौर पर तैयार किया गया है।

मीडिया का यह मनहूस प्रोपगंडा उसी समय खुल कर सामने आ गया था, जब टाइम्स नाव चैनल ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं अमीर जमाअते इस्लामी हिंद मौलाना जलालुद्दीन उमरी के हवाले से एक गलत रिपोर्ट प्रसारित की थी।

एनआईए की रिपोर्ट में बुनियादी तौर पर संगठन पर चार आरोप लगाए गए हैं। उनमें से एक आरोप, पैग़म्बर मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के बारे में बहुत ही ज़्यादा गलत शब्दों का इस्तेमाल करने वाले प्रोफेसर पर हमला करने का है। हालांकि पॉपुलर फ्रंट ने उसी वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, साफ तौर पर यह स्पष्ट कर दिया था कि संगठन इस मामले में बिल्कुल भी शरीक नहीं है। जहाँ तक नारथ घटना की बात है, तो वह संगठन के वार्षिक राष्ट्रीय

अभियान ''स्वस्थ लोग, स्वस्थ देश'' के तहत हमारे सदस्यों के द्वारा आयोजित किया गया एक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम था। जिसको जान बूझ कर हथियार की ट्रेनिंग की कहानी में बदल दिया गया। इस केस में केरल हाई कोर्ट ने यूएपीए की बात को खारिज कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ की गई एनआईए की अपील को मंजूर करने से इंकार कर दिया था। तीसरा आरोप यह लगाया गया कि संगठन सीरिया व इराक में सक्रिय आईएसआईएस के लिए मेम्बरों की भर्ती कर रहा है। 18 करोड़ मज़बूत भारतीय मुसलमानों में से केवल 60 लोगों के बारे में यह माना जा रहा है कि वे सीरिया या अफ़ग़ानिस्तान की तरफ गए हैं। जबकि हक़ीक़त यह है कि पॉपुलर फ्रंट ने अपने मेम्बरों को बहुत पहले ही आईएस जैसे रहस्यमय समूहों और सोशल मीडिया पर नौजवानों को बरगलाने की उनकी चाल से चौकन्ना कर दिया था। जब कभी भी ऐसे समूहों की ओर, किसी के अंदर ज़रा भी झुकाव नज़र आया, संगठन ने ऐसे लोगों को तुरंत संगठन से बाहर का रास्ता दिखा दिया। संगठन की इस पॉलीसी से सभी सदस्यों को समय पर ही एक सर्कुलर के द्वारा आगाह कर दिया गया था।

इसके अलावा मंजेरी में स्थापित धार्मिक शैक्षिक संस्था सत्य सारिणी को, हिंदुत्वा ताकतों के नस्लवादी प्रोपगंडे 'लव जिहाद' से जोड़ने की कोशिश भी पूर्ण रूप से बेबुनियाद है। इस्लाम क़बूल करने वाली महिला हादिया को, उसकी चाहत के अनुसार इस्लाम के अध्ययन के लिए सत्य सारिणी में दाखिल करने का फैसला केरल हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने दिया था। इसी कोर्ट ने ए.एस. ज़ैनब को हादिया की स्थानीय सरपरस्त के तौर पर तय किया था। उल्लेखनीय है कि सत्य सारिणी कोई धर्म परिवर्तन कराने की संस्था नहीं है; यह एक शैक्षिक संस्था है। लेकिन साथ ही यह बात भी याद रखनी चाहिए कि हर भारतीय नागरिक को अपनी मर्ज़ी से कोई भी धर्म क़बूल करने और उसके प्रचार व प्रसार का पूरा अधिकार हासिल है।

पॉपुलर फ्रंट एक ऐसा संगठन है जिसके हज़ारों मेम्बर हैं और जो देश के विभिन्न हिस्सों में काम कर रहा है। शिक्षा को बढ़ावा देने और गरीबी के खात्मे पर आधारित इसके विभिन्न कार्यक्रमों को सरकार द्वारा सराहा गया है। पॉपुलर फ्रंट का यह स्टैंड कि मौजूदा समय में देश के लिए सबसे बड़ा खतरा फासीवाद है, आज सबके सामने आ चुका है। सिर्फ इसी कारण यह संगठन केंद्र सरकार के निशाने पर है। संगठन अपने खिलाफ की जा रही तमाम कोशिशों को लोकतांत्रिक व कानूनी तरीकों से रोकने और उनके मुक़ाबले के लिए पूरी तरह से तैयार है।

जारी किया गया बयान
ई. अबूबकर,
चेयरमैन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया